नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

5 एक-एक घुसपैठिये देश से बाहर होंगे

6 नानाजी ने राष्ट्रोदय की संकल्पना की साकार

7 सैमसंग ने भारत में लॉन्च की गैलेक्सी एस26 सीरीज

8 द. अफ्रीका ने विंडीज को हराया

इजराइल में चलेगा यूपीआई

▶ बैठक में बड़ा समझौता ▶ साइबर सुरक्षा, यूपीआई समेत सहयोग के 17 करार ▶ भारतीय पोशाक में आए नेतन्याहू

60 लाख यहूदियों को श्रद्धांजलि दी

यरुशलम, 26 फरवरी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दो दिवसीय इजराइल यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों, कृषि, साइबर सुरक्षा, एआई तथा यूपीआई समेत कई क्षेत्रों में सहयोग के लिए करार किये और रिश्तों के विशेष रणनीतिक भागीदारी में बदलने के लिए घोषणाएं कीं.

इनमें पांच साल में 50,000 भारतीय कामगारों को इजराइल में कोटा देने, संयुक्त अनुसंधान में योगदान बढ़ाने और अकादमिक सहयोग फोरम के गठन की घोषणाएं भी शामिल हैं. प्रधानमंत्री की यात्रा की समाप्ति पर जारी साझा घोषणा पत्र में कहा गया है कि दोनों देशों ने 17 सहमति पत्रों/समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं. इसके अलावा 10 घोषणाएं भी की गयी हैं. दोनों नेताओं ने आतंकवाद को किसी भी स्वरूप और तरीके को अस्वीकार्य बताते हुए उसका मिलकर मुकाबला करने के प्रति दोनों देशों के संकल्प को दोहराया. भारत और इजराइल ने भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप कॉरिडोर और आई2यू2 (इंडिया-इजरायल-यूएई-यूएसए) पहल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया. दोनों प्रधानमंत्रियों ने अपने वार्ताकारों को मुक्त व्यापार समझौता वार्ता जल्द संपन्न करने के निर्देश दिये हैं और कहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश की संभावनाओं का पूरा उपयोग किया जाना चाहिये. संयुक्त घोषणापत्र में भारत इजरायल के बीच पिछले साल चार नवंबर को रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए हुए करार स्वागत किया गया है.

भारत-इजराइल के बीच खनिज अन्वेषण

संयुक्त घोषणा पत्र के अनुसार, दोनों देशों ने खनिज अन्वेषण में अत्याधुनिक भूगर्भ और एआई आधारित प्रौद्योगिकी, डाटा के आदान-प्रदान, निवेश और सतत संसाधनों के विकास के लिए सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये. दोनों पक्षों के बीच कृषि के क्षेत्र में प्रीसीजन फार्मिंग, उपग्रह आधारित सिंचाई, आधुनिक मशीनरी, कीट प्रबंधन और फसल कटाई के बाद के समाधानों बढ़ावा देने के लिए भारत-इजराइल कृषि नवाचार केंद्र (आईआईएनसीए) की स्थापना के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और इजरायल के समकक्ष संस्थान माशाव के बीच एमओयू हुआ है. भारत और इजराइल के लोगों के बीच धन के लेन-देन और एक-दूसरे के यहां भुगतान को आसान बनाने के लिए भारत के एनपीसीआई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म और इजरायल के संबंधित संगठन मसाव ने एक एमओयू किया है. इससे भारत के यूपीआई के जरिये इजराइल में भी लेनदेन संभव हो जायेगा.

> वाणिज्य और सेवाओं के क्षेत्र में मानव संसाधन के परस्पर आदान-प्रदान के लिए भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी है. रेस्त्रां क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र में कामगारों की आवाजाही के लिए भी अलग-अलग समझौते हुए हैं. इन कामगारों को रिटेल, सफाई, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, खाद्य प्रसंस्करण, आतिथ्य, रिसाइकिलिंग, कपड़ा, धातु, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, लकड़ी और कागज, प्लास्टिक और रबर जैसे क्षेत्रों में काम मिलेगा. अगले पांच साल में भारतीय कामगारों के लिए इजराइल में 50 हजार तक कोटा देने की घोषणा की गयी है. शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय और यरुशलम के हिब्रू विश्वविद्यालय के बीच फैकल्टी और छात्रों को एक-दूसरे के यहां भेजने के लिए एक एमओयू हुआ है. शिक्षा के क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल कर पठन-पाठन को बेहतर बनाने के लिए भी एक एमओयू हुआ है.

मप्र में निवेश हर मायने में फायदे का सौदा

देश के दिल से जुड़िए सीएम डॉ. यादव ने राजस्थान में निवेशकों को दिया न्यौता

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 26 फरवरी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मप्र आज देश के सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में अग्रणी बनकर उभरा है. मप्र में निवेश हर मायने में फायदे का सौदा है. देश के दिल से जुड़िए, विकास और अवसरों के केंद्र से जुड़िए. मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के मध्य में स्थित होने से मप्र व्यापार, उद्योग-धंधों की स्थापना और उत्पादों के निर्यात के लिए एक रणनीतिक केंद्र बनता जा रहा है. प्राकृतिक संसाधन, उद्योग-अनुकूल नीतियां, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर शासन-प्रशासन ये सभी कारक निवेशकों के लिए एक आदर्श वातावरण तैयार करते हैं.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरुवार को राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में इन्टरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपार्चुनिटि इन एमपी में स्थानीय निवेशकों, बिजनेस लीडर्स, उद्योगपतियों एवं विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मप्र को अनंत संभावनाओं का अनुपम केंद्र बताते हुए कहा कि वीरों की धरती राजस्थान के सभी निवेशकों का हीरों की धरती मप्र में स्वागत है, अभिनंदन है. उन्होंने कहा कि सदियों से हमारी साझा संस्कृति, व्यापार-व्यवसाय और साझा भविष्य का एक अटूट रिश्ता रहा है. हमारा आपसी संवाद नई संभावनाओं के विकास-विस्तार और देश की औद्योगिक क्षमता को नई... ▶ शेष पेज 12 पर

बड़े निवेश प्रस्तावों पर देंगे बड़ी रियायतें

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उन्होंने राज्य के उद्योग विभाग की कमान स्वयं ले ली हैं, जिससे प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ाने में कोई कठिनाई न आए और सभी मुद्दे सरलता के साथ समय रहते हल हो जाएं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मप्र सरकार ने औद्योगिक नीतियों को सरल बनाया है. इससे मध्यप्रदेश में निवेश और उद्योगों की स्थापना में तेजी आई है. राज्य सरकार निवेशकों को विशेष प्रोत्साहन भी प्रदान कर रही है. हमारी सरकार बड़े निवेश विभिन्न प्रस्तावों पर रियायतें भी दे रही है. हम छोटे-बड़े सभी निवेशकों को अपनी नीतियों से लाभान्वित कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश की अपार संभावनाएं हैं. टेक्सटाइल क्षेत्र में देश के सबसे पहले और सबसे बड़े पीएम मित्र पार्क का भूमि-पूजन भी मध्यप्रदेश में हो चुका है. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मिलकर हमारी सरकार इस क्षेत्र में और भी आगे बढ़ने के लिए तैयार है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मेवाड़ के निवेशकों को अपना उद्योग व्यवसाय शुरू करने के लिए मप्र आने का आमंत्रण भी दिया.

एक नजर में

कनाडा के प्रधानमंत्री आज से भारत दौरे पर

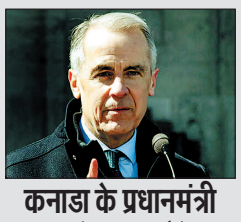

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 27 फरवरी से 2 मार्च 2026 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे. यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी. 27 फरवरी को वह मुंबई पहुंचेंगे, जहां वे व्यावसायिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे और भारत-कनाडा के उद्योगपतियों, वित्तीय विशेषज्ञों, नवप्रवर्तकों, शिक्षाविदों तथा कनाडाई पेंशन फंड प्रमुखों से मुलाकात करेंगे.

ईडी ने कुर्क की 7.17 करोड़ रुपए की संपत्ति

नयी दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े धन शोधन के एक मामले में 7.17 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है. ईडी के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय ने गुरुवार को कहा कि उसने गोवा के नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो द्वारा उगाचुकु सोलोमन उबाबुको, इन्फिनिटी जॉन उर्फ डेविड उर्फ वेलेंटाइन एजेज़ी और प्रसाद प्रकाश वाल्के के खिलाफ एनडीपीएस अधिनयम के तहत दर्ज शिकायत के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच शुरू की थी.

नशे में गाड़ी चलाई तो लाइसेंस होगा रद्द

नई दिल्ली, 26 फरवरी. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में हर साल लाखों लोगों की जान जाती है, इसलिए सरकार सड़क सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू कर रही है. उन्होंने बताया कि बार-बार शराब पीकर गाड़ी चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किया जाएगा. इसके अलावा लाइसेंस को ग्रेडेड पॉइंट सिस्टम में बदला जा रहा है, जिसमें 12 पॉइंट पूरा होने पर लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा.

गडकरी ने कहा कि सालाना करीब पांच लाख दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें 1.8 लाख लोग मारे जाते हैं. इनमें 72 प्रतिशत युवा और 10,119 बच्चे शामिल हैं. हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनने, तेज गति, गलत दिशा में गाड़ी चलाने और मोबाइल फोन उपयोग करने जैसी आदतें दुर्घटनाओं के मुख्य कारण हैं. सड़क सुरक्षा सुधार के लिए रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल मानक और बस बॉडी कोड में बदलाव किए गए हैं.

> सरकार ने प्रधानमंत्री राहत योजना और राहवीर योजना शुरू की हैं, जिनके तहत दुर्घटना पीड़ित को कैशलेस उपचार और मदद करने वाले को पुरस्कार मिलेगा. इसके अलावा उच्च दुर्घटना वाले जिलों और ब्लैक स्पॉट की पहचान कर सुधार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. गडकरी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं से देश की लगभग तीन प्रतिशत जीडीपी का नुकसान होता है और इसे कम करने के लिए कानून का पालन, जागरूकता और शिक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. जनता को नियमों का सम्मान करने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देना होगा.

एनसीईआरटी मामले में न्यायपालिका के आदेश का पालन किया जाएगा: प्रधान

नयी दिल्ली. शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की आठवीं कक्षा की समाज विज्ञान की पुस्तक विवाद पर कहा कि सरकार न्यायपालिका का पूरा सम्मान करती है और उच्चतम न्यायालय के सभी निर्देशों का पालन किया जायेगा. श्री प्रधान ने उच्चतम न्यायालय के एनसीईआरटी की कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के पुनर्मुद्रण और डिजिटल प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश पर गुरूवार को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'हम न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हैं.

1 मार्च से व्हाट्सएप और अन्य ऐप्स सिर्फ एक्टिव सिम पर काम करेंगे

▶ नंबर बदलने पर बंद हो सकता है अकाउंट

नई दिल्ली, 26 फरवरी. भारत सरकार ने 1 मार्च 2026 से व्हाट्सप्प और अन्य मैसेजिंग ऐप्स पर नया सिम-बाइंडिंग नियम लागू करने का ऐलान किया है. इसके तहत जिस नंबर से आपने अकाउंट बनाया है, वही सिम हमेशा फोन में एक्टिव रहनी चाहिए. अगर सिम हटाई जाती है, किसी अन्य फोन में लगाई जाती है या बंद हो जाती है, तो ऐप काम नहीं करेगा और वेरिफिकेशन फिर से करना पड़ सकता है.

अब तक ऐप्स में केवल ओटीपी से एक बार लॉगिन होता था, लेकिन नया नियम हर समय स्क्रीन की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा. सरकार का कहना है कि यह बदलाव डिजिटल सुरक्षा और साइबर अपराध रोकने के लिए है. हर अकाउंट को एक वेरिफाइड सिम से जोड़ने से फर्जी नंबर और फ्रॉड अकाउंट पहचानना आसान होगा.

षड़यंत्र रचकर यात्री बसों के जरिए 9 करोड़ की टैक्स चोरी

जबलपुर. षडयंत्र रच कर यात्री बसों के जरिए 9 करोड़ की टैक्स चोरी करने पर जबलपुर ईओडब्ल्यू ने बस मालिक एवं परिवहन विभाग के कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. जानकारी के मुताबिक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, जबलपुर में प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल से शिकायत मिली कि संजय केशवानी एवं साधना केशवानी के नाम पर दर्ज यात्री वाहनों व्दारा बकाया टैक्स होने पर भी वाहनों का परमिट, फिटनेस जिला परिवहन कार्यालय डिंडौरी से जारी करने के संबंध में शिकायत की गई थी.

हाईकोर्ट : सशस्त्र बल कर्मियों की दिव्यांगता पेंशन पर अहम फैसला

नई दिल्ली, 26 फरवरी. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सैनिक या अधिकारी की बीमारी को सिर्फ 'लाइफस्टाइल डिसऑर्डर' कहकर दिव्यांगता पेंशन रोकना गलत है, चाहे वह पीस पोस्टिंग में हुई हो या ऑपरेशनल क्षेत्र में. जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड अधिकारी की याचिका मंजूर की, जिनकी पेंशन पहले खारिज की गई थी.

अधिकारी को *हाई ब्लड प्रेशर और कोरोनरी आर्टरी डिजीज थी.

कोर्ट ने कहा कि गैर-ऑपरेशनल क्षेत्र में भी सैन्य सेवा तनावपूर्ण होती है और इससे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं. मेडिकल बोर्ड ने माना कि अधिकारी की बीमारियां उनकी लापरवाही या गलत आदतों की वजह से नहीं हुई. इसलिए वजन, धूम्रपान या शराब जैसी वजहों पर पेंशन रोकना तर्कसंगत नहीं.

टेक्नोलॉजी से बदलेगी रेलवे की तस्वीर

एमपी के स्टेशन बनेंगे विश्वस्तरीय

नई दिल्ली, 26 फरवरी. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मध्य प्रदेश के कई रेलवे स्टेशनों को विश्वस्तरीय बनाने का काम तेजी से जारी है. भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित एक दर्जन से अधिक स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग किया जाएगा. राज्य को महाराष्ट्र और दक्षिण भारत से बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है.

रेल मंत्री ने रेलवे में 52 हफ्तों में 52 सुधार लागू करने की योजना का भी ऐलान किया. उन्होंने कहा कि रेलवे अब हादसे के बाद नहीं, बल्कि हादसे से पहले खतरे की पहचान करने वाले 'प्रो-एक्टिव' सिस्टम की ओर बढ़ रहा है. इसके तहत हाथियों की ट्रैक पर मौजूदगी पहचानने वाला एआई सिस्टम, डिब्बों में आग की शुरुआती चेतावनी, ड्रोन से टूटी पटरी की पहचान, पटरियों के स्ट्रेस मॉनिटरिंग सिस्टम और कोहरे में रुकावट पहचानने जैसी तकनीकें लागू की जाएंगी.

> साथ ही मुआवजा मामलों के त्वरित निपटारे के लिए इलेक्ट्रॉनिक रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल (ईआरसीटी) सिस्टम शुरू किया गया है. अब रेलवे हादसों, माल नुकसान या किराया विवाद से जुड़े दावे पूरी तरह ऑनलाइन दर्ज और सुने जाएंगे. ई-हियरिंग, डिजिटल नोटिस और स्वतः केस अलोकेशन जैसी सुविधाओं से प्रक्रिया पारदर्शी और तेज होगी.

दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना लोकतंत्र का मूल आधार

नयी दिल्ली 26 फरवरी. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अपनी भावनाओं का सम्मान करना और इस तरह के आदान-प्रदान से राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है.

श्री राधाकृष्णन ने गुरूवार को श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में कहा कि विश्वविद्यालयों को भले ही बुनियादी ढांचे और अकादमिक उत्कृष्टता के लिए जाना जाता हो, लेकिन उनकी सच्ची विरासत उनके स्नातकों के चरित्र और योगदान में झलकती है. उन्होंने 1948 में स्थापित कश्मीर विश्वविद्यालय की गौरवशाली विरासत और बढ़ते अकादमिक प्रभाव की सराहना की.

उन्होंने छात्रों से निरंतर अनुकूलन करने, नए कौशल हासिल करने और नवाचार को अपनाने का आग्रह किया. भारत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवप्रवर्तक के रूप में उभरने पर जोर देते हुए उन्होंने युवाओं को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप स्वदेशी नवाचारों को आगे बढ़ाने और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया. उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों जिनमें श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का विस्तार और चेनाब रेल पुल जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाएं शामिल हैं, उन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह पहल नए अवसर पैदा करती हैं.

> उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र में दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अपनी भावनाओं का सम्मान करना, और इस तरह के आदान-प्रदान से राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है. उपराष्ट्रपति ने युवाओं से नशे से दूर रहने और सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करने का आग्रह किया.

निर्देश ▶ न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई एनसीईआरटी की किताब पर रोक

नई दिल्ली, 26 फरवरी. एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े आपत्तिजनक उल्लेखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. गुरुवार को सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने इसे न्यायपालिका को बदनाम करने की सोची-समझी साजिश करार दिया और बाजार से किताब को वापस लेने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच की बात कही है और इससे एक दिन पहले ही किताब के खास चैप्टर पर आपत्ति जताई थी. कोर्ट ने कहा था कि अदालत को बदनाम नहीं करने दिया जाएगा, हालांकि कोर्ट की आपत्ति के बाद एनसीईआरटी ने किताब फिर लिखने का फैसला किया है.

सुप्रीम कोर्ट में एनसीईआरटी की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस सुओ मोटो केस में हम माफी मांगते हैं. इस पर सीजेआई ने कहा कि मीडिया में हमारे दोस्तों ने यह नोटिस भेजा और इसमें माफी का एक शब्द नहीं है.

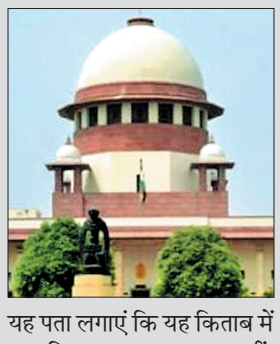

उन्होंने कहा, 'यह हमारी संस्थागत जिम्मेदारी है कि हम यह पता लगाएं कि यह किताब में प्रकाशित हुआ था या नहीं. रजिस्ट्रार जनरल को भेजे गए संदेश में संबंधित विभाग इसका बचाव कर रहा था. यह एक गहरी साजिश थी.

सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि चैप्टर तैयार करने वाले दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. वे कभी यूजीसी या किसी मंत्रालय के साथ काम नहीं कर सकेंगे. इसके बाद सीजेआई ने कहा, 'यह तो बहुत आसान होगा और वो बच निकलेंगे. उन्होंने गोली चलाई और न्यायपालिका का खून बह रहा है.' तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि 32 कॉपी जो बाजार में गई थीं, उन्हें वापस ले लिया गया है और पूरी पुस्तक की समीक्षा की जाएगी.

> एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सोशल साइंस की किताब में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' से जुड़े चैप्टर को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले पर सख्त नाराजगी जताई है. सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी ने इस विषय पर स्पष्ट जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं. सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने पूछा कि किताब की छपाई और सामग्री की निगरानी कौन कर रहा था. उन्होंने आश्चर्य जताया कि आठवीं कक्षा के छात्रों के पाठ्यक्रम में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय को किस आधार पर शामिल किया गया.

भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार पर 10 हजार करोड़ रुपए के घोटाले का लगाया आरोप

सीबीआई जांच की मांग की

कर्नाटक. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर 10 हजार करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है और मामले की सीबीआई जांच की मांग की है. भाजपा प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने कहा कि राज्य में पिछले वर्षों में वित्तीय अनियमितताओं के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें शराब, भूमि और खनन संबंधित घोटाले शामिल हैं. उन्होंने बताया कि 2024 में इंडिया गठबंधन नेता रामेश्वर उरांव द्वारा भेजे गए पत्र में इस राशि के उपयोग का स्पष्ट हिसाब मांगा गया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.